STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in the Three Hundred and Twenty-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; AND THE MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, with your permission, I wish to lay a statement regarding Status of implementation of recommendations contained in the Three Hundred and Twenty-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that a Supplementary List of Business has been issued by the Secretariat today regarding *suo motu* statement to be made by the hon. Home Minister at 11.30 am regarding avalanche in Chamoli district of Uttarakhand. The Supplementary List has been uploaded on the Rajya Sabha website and the Members Login Portal.

The statement to be made will also be uploaded on the Members Login Portal as soon as it is taken up in the House.

Now, we will take up Matters to be raised with the permission of Chair. Shri Mahesh Poddar.

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, कल सदन की शुरुआत में जो कुछ भी हुआ, वह बहुत निंदनीय है। We all have respect and regard for you and, especially, the Chair. And, as a person also, we have got a lot of respect and regard for you. Whatever had happened yesterday is unacceptable. Throwing aspersions on the Chair is not at all acceptable. यह बहुत निंदनीय है। मैं वि.विजयसाई रेड्डी जी से आग्रह करता हूं कि वे कृपया क्षमा प्रार्थना करें और मैं अपनी तरफ से भी क्षमा प्रार्थना करता हूं।

MR. CHAIRMAN: See, things are not made out of request. Leave it.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I may kindly be permitted to submit something.

Sir, my intention was never to bring any disrepute or make the Chair dysfunctional. I am no one to make the hon. Chairman of the Rajya Sabha dysfunctional. Yesterday's episode was because I was in a state of anguish. Therefore, I wish to take back my words. I sincerely regret for the comments made by me yesterday. They were unintended and made on spur of anguish as I had become emotional. And, I assure you, Sir, I had no intention to hurt you or cast aspersions on the Chair.

I, therefore, regret once again and assure you that it will not be repeated once again. Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay, leave it. The matter is closed now.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to ban use of objectionable language/ derogatory content on OTT platforms

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): सभापति महोदय, देश में इंटरनेट की सुलभता के साथ-साथ Netflix जैसे अनेक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सूचना और मनोरंजन के नए माध्यम के रूप में उभरे हैं। कोरोना महामारी के कारण लगातार लॉकडाउन और थिएटर्स के बंद होने की वजह से भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच काफी बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ-साथ एक खतरा भी बढ़ा है, एक विसंगति भी आई है, जिससे समाज और हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर दूरगामी, नकारात्मक और विकृत प्रभाव पड़ने की संभावना बलवती हो गई है। देश का एक बड़ा धार्मिक वर्ग सांस्कृतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है, लेकिन मेरी चिंता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में उपलब्ध सामग्री द्वारा भारतीय सामाजिक मूल्यों पर हो रहे आघात को लेकर भी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भाषा और कंटेट में sex discrimination ...(**व्यवधान**)...अथवा gender discrimination साफ झलकता है। एक तरफ तो हम स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक माध्यमों पर मां-बहन की गालियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्त्री-पुरुषों के जननांगों की चर्चा सार्वजनिक रूप में कराई जा रही है।

महोदय, हिंदी या अंग्रेज़ी या कोई और अन्य भाषा हो, उसमें यह भी ग़ौर करने योग्य है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील फूहड़ भाषाओं के इस्तेमाल के क्रम में नारी गरिमा को ही बार-बार तार-तार किया जाता है, मानो कि पुरुष भोक्ता हो और नारी भोग्या। मैं अंत में बोलना चाहता हूं कि इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के रेग्युलेशन की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी जा चुकी है। इसमें देरी करने की संभावना नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार यथाशीघ्र और प्रभावी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सहित इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना और मनोरंजन के सभी माध्यम समुचित...(**व्यवधान**)... नियंत्रित करे।